हम ने डीपीईपी और सर्व-शिक्षा अभियान मे मिलाकर 5100 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की है। अब मूल प्रश्न में इस बात का संकेत नहीं था कि कहां भवन नहीं है, किस गांव में नहीं है - यह जानकारी प्राप्त करके आपको दी जा सकती है। इस समय वह जानकारी मैं नहीं दे सकता कि कितने भवन-विहीन स्कूल्स हैं। हां, कितने भवन हमने बनाए हैं, वह जरूर मैंने आपको जानकारी दे दी है। हम कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, कितने भवनविहीन हैं, आपको योगदान उस में रहा है और आप उस बारे में बेहतर जानते होंगे। हम तो भवन बना रहे हैं और उसकी जानकारी आपको दे दी है। जहां तक ''मिड डे मील'' का संबंध है, मैं, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इस समय 18 राज्यों में यह स्कीम लागू है जिसमें से 10 राज्यों में पूर्णत: पका-पकाया भोजन देने की व्यवस्था है, एक में आंशिक रूप से दिया जा रहा है और एक में अभी स्टार्ट किया है और बाकी में भी आंशिक रूप से दिया जा रहा है।

**श्री सभापति:** यह जवाब आपको प्रश्न 246 के उत्तर में देना पड़ेगा।

**श्री मोती लाल वोरा:** माननीय सभापति महोदय, माननीय विद्वान मंत्री जी से तो यह अपेक्षा की जाती है कि जब वे सदन में आएं इस बात की जानकारी लेकर आएं कि कितने भवन नहीं बने हैं, कितने स्कूल्स भवन-विहीन हैं।

**डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी:** श्रीमन्, उनकी जानकारी इनके पास पहले से है क्योंकि ये भवन-विहीन छोड़कर आए थे।

**श्री मोती लाल वोरा:** माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे जानकारी है कि जो स्कूल्स झाड़ के नीचे लगते है और कई स्कूलों में शिक्षक हैं ही नहीं, तो माननीय मंत्री महोदय आने वाले समय में इस बात की व्यवस्था करेंगे कि भवन-विहीन स्कूलों में भवन बन जाएं और जहां पर शिक्षक नहीं हैं, वहां शिक्षक हो जाएं। महोदय, आखिरी प्रश्न मैंने घटिया किस्म के ''मिड डे मील'' का पूछ था।

**श्री सभापति:** मिड डे मील का क्वैश्चन आगे आ रहा है। प्रश्न संख्या-243.

## Increase in college fees

*243. DR. C. NARAYANA REDDY: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to increase fees of college students of general and professional courses;

(b) if so, by when it is likely to be implemented; and

(c) what will be the position of subsidies?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) to (c) The government has asked the University Grants Commission (UGC) recently for rationalisation of fees in University/College System in general, with particular reference to the institutions funded by the Central Government through the UGC. The Government does not consider the amount spent on higher education as a subsidy. It is an investment in human resource development and there has been a consistent increase in plan allocations for Higher Education.

DR. C. NARAYANA REDDY: Mr. Chairman, Sir, I would like to know from the hon. Minister what will be the percentage of enhancement of fees, and whether it is a fact that the Ministry of Finance has proposed an enhancement of 20 to 33 per cent.

डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन्, इसमें विभिन्न समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समितियां बनाई हैं और फाइनेंस कमीशन ने भी इस बारे में सिफारिशें दी हैं और यह कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय अपने खर्चे का एक निश्चित 15 से 20 प्रतिशत तक की व्यवस्था खुद करें। यह हमेशा से होता रहा है, जब मैं पढ़ता था तब, मेरे पिता जी पढ़ते थे तब और जब मेरी बेटियां पढ़ती थीं तब और जब शायद उनके बच्चे पढ़ेंगे तबसे फीस वही चली आ रही है, 110-112 साल से फीस में कोई वृद्धि नहीं हुई है। महोदय, आजादी के पहले भी 20 प्रतिशत तक खर्चा विश्वविद्यालय अपने अनुदानों से, बाहर से दान से या फीस से इकट्ठा करते थे। आज भी लगभग उतना ही व्यय विश्वविद्यालय एकत्रित करें तो बहुत कुछ राहत मिल सकती है। हमारी भी इच्छा यही है, सोचना यही है कि फीस इस प्रकार से बढ़ाई जाए, जिससे विश्वविद्यालयों के पास कुछ आंतरिक साधनों की उपलब्धि हो और हम यही प्रयत्न कर रहे हैं। लोगों से हम अनुरोध कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे इस दिशा में कदम उठाएं। तो कोई बेतहाशा वृद्धि होने का सवाल नहीं है और सरकार के खर्च में भी, उनको दी जाने वाली राशि में भी किसी प्रकार की कटौती का सवाल नहीं है।

DR. C. NARAYANA REDDY: My second supplementary is: Does the enhancement in fee not affect the enrolment of students for higher education, which is already, according to experts, as low as 6.5 per cent? Does the Government ensure increase in the enrolment of students at the level of 21 per cent which is the average for a developing country?

**डा॰ मुरली मनोहर जोशी:** सभापति जी, इसके लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं हैं। मुक्त विद्यालय, उसके साथ-साथ इंदिरा गांधी ओपेन यूनिवर्सिटी इस दिशा में बहुत काम कर रही हैं। हम ज्ञानवाणी, ज्ञानदर्शन और अब आगे चलकर विद्या-वाहिनी ऐसी स्कीमें चला रहे हैं, जिससे डिस्टेन्स एजुकेशन के द्वारा लोगों को शिक्षा मिले। इसके साथ ही एजुकेशन सैटलाइट की भी एक तजवीज की है और अगर वह बन जाती है तो उसके माध्यम से हरेक क्षेत्र में, हरेक गांव में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, सबकी व्यवस्था होगी। अभी इग्नू की ओर से तकनीकी शिक्षा चैनल शुरू हो गया है, जो प्रतिदिन शुरू हो गया है। इसलिए चाहे वह तकनीकी शिक्षा हो या सामान्य शिक्षा हो, आज इस बारे में किसी की शिकायत नहीं मिल सकेगी कि उसे पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है।

†**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज:** चेयरमेन साहब, मैं यह ख्वाइश करता हूं कि ऑनरेबिल मिनिस्टर जो बड़ी काबलियत रखते हैं, इस पूरे इश्यू को नए सिरे से सोचें।

†**श्री सभापति:** आप क्वैश्चन कीजिए।

†**प्रो॰ सैफुद्दीन सोज:** सर, मैं सवाल कर रहा हूं। यह जो प्रोफेशनल कॉलेजों और दूसरे इदारों से जो फीस बढ़ाने की एक तरह से मांग है और इन्होंने रेस्पोन्स भी किया है, उसके पीछे एक सवाल छुपा है कि हमने समाज को बांटा है। गरीब बच्चे का क्वालिटी एजुकेशन का कोई ताल्लुक नहीं रखता और गरीब बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं वहां न चटाई है, न ब्लैकबोर्ड है, न पढ़ाने का इंतजाम है। यह हमने खुद किया है क्योंकि अभी हमने वह गहरी नजर तालीम पर नहीं की है। तो मैं यह सोच रहा हूं कि इस सवाल पर मिनिस्टर जोशी साहब तवज्जुह दें कि जिनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, बड़े कॉलेजों में जरूर पढ़ें लेकिन वे फीस भी दें क्योंकि वे एफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके तनासुब में गरीब बच्चों को, जो पावरटी लाइन के नीचे हैं जिनका बहुत बुरा हाल है, इन गरीब बच्चों को इस देश में वह तालीम मिले, जो हुकूमत ने स्टेट्यूटरी अंदाज में तैयार की होगी। क्या इस सवाल में गहरा जायजा लेने के लिए कोई कदम आप उठाएंगे?

پروفیسر سیف الدین سوز : چیئرمین صاحب، میں یہ خواہش کرتا ہوں کہ آنریبل منسٹر جو بڑی قابلیت رکھتے ہیں، اس پورے ایشو کو نئے سرے سے سوچیں۔

شری سبھاپتی : آپ کوئسچن کیجئے۔

پروفیسر سیف الدین سوز : سر، میں سوال کر رہا ہوں، یہ جو پروفیشنل کالجوں اور دوسرے اداروں سے جو فیس بڑھانے کی ایک طرح سے مانگ ہے، اور انہوں نے ریسپانس بھی کیا ہے، اسکے پیچھے ایک سوال چھپا ہے کہ ہم نے سماج کو بانٹا ہے۔ غریب بچے کا کوالیٹی ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور غریب بچے جن اسکولوں میں جاتے ہیں وہاں نہ چٹائی ہے، نہ بلیک بورڈ ہے نہ پڑھانے کا انتظام ہے۔ یہ ہم نے خود کیا ہے کیونکہ ابھی ہم نے وہ گہری نظر تعلیم پر نہیں کی ہے، تو میں یہ سوچ

†Transliteration of Urdu Script.

رہا ہوں کہ اس سوال پر منسٹر جوشی صاحب توجہ دیں کہ جن کو کوالیٹی ایجوکیشن چاہئے ، بڑے کالجوں میں ضرور پڑھیں ، لیکن وہ فیس بھی دیں کیونکہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں ، لیکن اس کے تناسب میں غریب بچوں کو جو پاورٹی لائن کے نیچے ہیں ان کا بہت برا حال ہے۔ لیکن غریب بچوں کو اس دیش میں وہ تعلیم ملے جو حکومت نے اسٹیچوٹری انداز میں تیار کی ہوگی ۔ کیا اس سوال میں گہرا جائزہ لینے کے لئے کوئی قدم آپ اٹھائیں گے؟

**डा॰ मुरली मनोहर जोशी:** सभापति जी, इस पर बराबर जायजे लिए जा रहे हैं और यह सरकार का सरोकार है कि हर मेधावी बच्चे को, चाहे वह गरीब क्यों न हो उसे शिक्षा से किसी भी हाल में महरूम न रखा जाए। आज उनके लिए वजीफे की, फीस में कमी की और फीस माफी की भी पूरी गुंजाइशें रखी जा रही हैं। इसके साथ साथ उनके लिए सस्ते दरों पर ऋण मिल सके, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है और चार लाख रुपए तक का लोन भी उन्हें मिल सकता है। उनके ऊपर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, हमने रोका नहीं है। ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं ताकि जो बच्चे एफोर्ड नहीं कर सकते वे भी इसी रास्ते से अपने आपको शिक्षा के रास्ते पर ला सकें। साथ ही, जैसा मैंने अर्ज किया, हमने वह रास्ते खोल दिए हैं, जिसमें अगर वे बच्चे जा नहीं सकते, एफोर्ड नहीं कर सकते, तकनीकी शिक्षा भी लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्वालिटी एजुकेशन के प्रोग्राम हम साया कर रहे हैं अपने इस एकलव्य चैनल के माध्यम से। पूरे इंतजामात हैं इसलिए अब यह सवाल नहीं उठता है कि हिन्दुस्तान में यह शिकायत आए कि कोई बच्चा, जो किसी भी किस्म की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उनके लिए कोई रास्ता खुला नहीं है।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: After the judgement of the Supreme Court in T.A. Pai's case, the self-financing colleges in Tamil Nadu and Kerala are collecting exorbitant money as capitation fee. It is a known fact. It is social justice, as far as Tamil Nadu is concerned. I would like to know whether the Govenrment is having any proposal to give direction to private colleges, self-financing colleges not to collect a huge amount as capitation fee. May I also know from the Minister whether the Government is having any proposal to file a review petition in the Supreme Court against the judgement in T.A. Pai's case?

**डा॰ मुरली मनोहर जोशी:** श्रीमन, टी॰ए॰ पाई के केस के बाद जो स्थिति पैदा हुई है, उसका जायज़ा लेने के लिए और उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक कमेटी बना दी है जो बहुत जल्दी अपनी सिफारिश देगी और मुख्तलिफ सूबों से, डिफरेंट स्टेट्स के सचिवों को बुलाकर उनके साथ भी एक पालिसी बना ली है कि इस साल ऐडमिशन कैसे होंगे। इस पर हम काफी संजीदगी से राय ले रहे हैं और जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी, हम उस पर अमल करेंगे। मैं यह बताना चाहता हूं कि उस जजमेंट में यह बात साफ लिखी गई है कि ऐजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन नहीं होगा, शिक्षा का कमर्शियलाइजेशन नहीं होगा। दूसरी बात यह भी कही गई है कि एक रीज़नेबल सरप्लस सब स्कूलों के पास होगा क्योंकि अगर वे रीज़नेबल सरप्लस नहीं

रखेंगे तो वे अपना रख-मुनाफाखोरी नहीं होगी ऐजुकेशन में, यह साफ लिखा हुआ है। इसके तहत हमने एक कमेटी बनाई है ताकि वह इस बारे में हमें पूरी सिफारिशें दे और उसके बाद हम एक गाइडलाइंस ईश्यू करेंगे।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: Thank you very much for constituting a committee.

SHRIMATI VANGA GEETHA: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has just now said that the college fee for higher eduction has been enhanced. I would like to know from the hon. Minister, through you, Sir, what steps the Government is contemplating to upgrade the quality of education.

**डा॰ मुरली मनोहर जोशी:** श्रीमन् वैसे तो यह सवाल इससे उत्पन्न नहीं होता क्योंकि यह फीस से संबंधित है, लेकिन क्वालिटी के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। ''नेक'' नाम की एक संस्था बनी हुई है जो सब विद्यालयों का परीक्षण करती है और हमने यह तय कर लिया है कि हर विश्वविद्यालय और हर प्रोफेशनल कालेज को एक निश्चित अवधि के अंदर अपना परीक्षण करा लेना पड़ेगा और अगर वह परीक्षण नहीं कराएगा तो उसको सूची से बाहर कर दिया जाएगा।

## पशुओं में भुखमरी और कुपोषण

*244. **श्रीमती सरोज दुबे:**††
**श्री मूल चन्द मीणा:**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में पशु आंशिक भुखमरी और व्यापक कुपोषण के शिकार हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार पशुओं को भुखमरी और कुपोषण से बचाने के लिए क्या-क्या कदम उठाने जा रही है?

**कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह):** (क) और (ख) देश में चारे की उपलब्धता की काफी कमी है। यह कमी सूखे और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान और भी बढ़ जाती है जैसा कि मौजूदा सूखे से अनुभव हुआ है।

(ग) आहार और चारे की कमी को कम करने के लिए निम्न प्रबंध किए हैं:-

---

††सभा में यह प्रश्न श्रीमती सरोज दुबे द्वारा पूछा गया।